

**पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना**

प्रेषक,

विनय कुमार,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना- 15, दिनांक- 17/01/2015

URGENT

माननीय उच्च
न्यायालय के
अवमाननावाद
से संबंधित।

विषय :- राज्य स्थित गोशालाओं की परिसम्पत्तियों एवं अतिक्रमण/अवैध दखल (अनधिकृत कब्जा) की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।
प्रसंग :- माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अवमानना वाद संख्या 590/ 2014 में दिनांक 16.01.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन न्यायादेश के आलोक में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार के पत्र संख्या-86 दिनांक-05.03.2012, सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0-127 दिनांक-28.06.2014 एवं निदेशक, पशुपालन के पत्रांक 234 दिनांक 16.12.2014 के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित निबंधित कुल 87 (सतासी) गोशालाओं के परिसम्पत्ति से अतिक्रमण तथा अनधिकृत दखल को हटाने के लिये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित "बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम-2009" तथा इससे संबंधित नियमावली यथा "बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली-2010" के अन्तर्गत सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई का स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बावजूद कृत कार्रवाई से अनभिज्ञता के कारण दिनांक 16.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना वाद संख्या 590/ 2014 की सुनवाई के दौरान विभाग द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा काफी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा सुनवाई की अगली तिथि 23.01.2015 को इस संबंध में स्पष्ट विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में निम्नांकित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन अनिवार्यतः

